शोध मंथन Vol. XIV No.II Apr.-June 2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

घरेलू महिला कामगारों पर कोरोना महामारी का प्रभावः दिल्ली का एक अध्ययन

प्राप्तिः 22.05.2023
स्वीकृतः 25.06.2023

40

नयनतारा सिंह
शोधार्थी
महिला विकास अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली

डॉ० अजीत कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
एमिटी विश्वविद्यालय, हरियाणा
ईमेलः *ajeetbhu07@gmail.com*

सारांश

प्रस्तुत शोध आलेख मुख्य रूप से एक खोजपूर्ण अध्ययन पर आधारित है। जहाँ कोरोना महामारी जैसी प्राकृतिक विपदा के प्रभाव को समाज के हाशिए पर रहने वाले महिलाओं के संदर्भ में जानने का प्रयास किया गया है। इसके तहत इस अध्ययन में मुख्यतः घरेलू महिला कामगारों के अनुभव एवं परिस्थितियों को अध्ययन में शामिल किया गय है, ताकि कोरोना महामारी के दौरान उनके रोजगार पर पड़ने वाले संकट एवं उसके प्रभाव को व्यापकता में समझा जा सके।

कोरोना महामारी के कारण लगाए गए पूर्ण एवं आंशिक लॉकडाउन के दौरान असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले या घरेलू कामगारों के जीवन यापन करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्थिति पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ा? इन सभी पहलुओं की पड़ताल इस शोध अध्ययन में करने की कोशिश की गई है। तथा इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य को समझने के लिए दिल्ली में घरेलु कामकाज से जुड़ी कुल 10 महिलाओं से व्यक्तिगत संपर्क करके तथा उनका व्यक्तिगत–साक्षात्कार लेकर इस शोध–अध्ययन को पूरा किया गया है।

मुख्य बिन्दु

घरेलू महिला कामगार, कोरोना महामारी, दिल्ली, आपदा, जेंडर।

किसी भी आपदा या महामारी का यूँ तो समाज पर चौतरफा प्रभाव होता है। लेकिन, यदि इसे जेंडर के नजरिये से देखा जाय तो महिलाओं पर इसका असर ज्यादा व्यापक पड़ता है, खासकर गरीब एवं वंचित वर्ग से सम्बंधित महिलाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। आपदाओं एवं महामारी के ऐतिहासिक विवेचन के माध्यम से यह बात स्पष्ट की जा सकती है।

समाज के हाशिये पर स्थित महिलाओं को महामारी के संकट काल में दो स्तरों पर लड़ना पड़ता है,

एक महामारी से एवं दूसरा उसके सामाजिक–आर्थिक दुष्प्रभाव से। वैसे तो महिलाओं को हमेशा से समाज में दोयम दर्जे का माना गया है। भारतीय समाज में अधिकतर महिलाएं अपने परिवारों में भी इस त्रासदी को झेलती है, जहां माँ–बाप का नजरिया भी बेटा और बेटी के लिए अलग–अलग होता है। चाहे खाना हो, पहनना हो, पढ़ना हो वहां पहली प्राथमिकता बेटों का होता है तथा बेटियाँ द्वितीयक (सेकेंडरी) स्थान पर होती है। हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए यहाँ अधिकतर पीड़ा महिलाओं को सहना पड़ता है।

लगभग पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस के नकारात्मक प्रभाव से पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी है। दुनिया में इस महामारी से अब तक लाखों लोग अपनी जान गवां चुके हैं। करोड़ों लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन सबका असर वैसे तो पूरे समाज पर पड़ा है, लेकिन ऐसे हालात में महिलाएं विशेष तौर पर प्रभावित हुई हैं।

किसी भी आपदा या महामारी का अपना सामाजिक प्रभाव भी होता है। जिससे महिलायें सबसे अधिक प्रभावित होती है। 19वीं एवं 20वीं सदी में भारत में फैले महामारी एवं आकाल का सबसे व्यापक प्रभाव महिलाओं ने ही झेला। जहाँ उन्हें महामारी से उत्पन्न संकट के साथ ही साथ भावनात्मक रूप से भी त्रासदी का सामना करना पड़ा। एशिया और पैसिफिक के 'जेंडर इन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन' नामक संस्था के अनुसार, किसी भी महामारी के समय महिलाओं पर बोझ बढ़ जाता है। उन्हें घर में बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल का अवैतनिक कार्य भी बढ़ जाता है। स्कूलों में छुट्टियां किये जाने पर कम उम्र की लड़कियों को भी घर के बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल में शामिल किया जाता है। घर के बाहर भी देखें तो महामारी के समय स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ कई गुना बढ़ जाता है और इसका बड़ा बोझ भी महिलाएं ही उठातीं हैं।

वर्तमान समय में दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं और इससे जुड़े सामाजिक संस्थाओं में कुल रोजगार प्राप्त लोगों में से 70 प्रतिशत महिलायें हैं, फिर भी इस क्षेत्र में वेतन में लैंगिक असमानता 28 प्रतिशत से भी अधिक है।

महामारी के समय समाज में फैले तनाव का खामियाजा भी सबसे अधिक महिलायें ही भुगततीं हैं और बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। एबोला वायरस के विस्तार के समय किये गए एक अध्ययन में यह देखा गया था कि विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलायें पुरुषों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होती हैं और उनकी सुरक्षा दांव पर लगी होती है। एबोला एवं जिका वायरस के विस्तार के समय किये गए एक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महामारी के समय महिलाओं का सामान्य स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य सेवायें सामान्य समस्याओं को नजरअंदाज करती हैं। 'जेंडर इन ह्यूमैनिटेरियन एक्शन' के अनुसार, किसी भी आपदा या महामारी में महिलाओं की व्यापक भूमिका के बाद भी इससे संबंधित योजना बनाने वाले या नीति निर्धारण करने वाले समूह में उच्च स्तर पर महिलाओं की भागीदारी नहीं रहती।[1]

उपरोक्त तथ्यात्मक बातों के सन्दर्भ में इस विषय पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन अपेक्षित है। जिसको आधार बनाकर, करोना महामारी के प्रभाव को दिल्ली में घरेलू सहायक के रूप में काम

करने वाली असंगठित क्षेत्र की महिलाओं पर इस महामारी के प्रभाव का विश्लेषण एक केस स्टडी के रूप में किया गया है।

भारत की राजधानी और देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य दिल्ली में करीब 97.5% शहरी आबादी निवास करती है। जहां मई 2020 से अगस्त 2020 के बीच अनलॉक के पहले तीन चरणों के दौरन श्रम बाल भागीदारी दर 33% के साथ सबसे कम और बेरोज़गारी दर 23.3% के साथ सबसे अधिक रही थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएसआईई) के आंकड़ों में बताया गया है कि एलएफपीआर भारत में काम करने वाले सभी उम्र के लोगों का अनुपात है, जिनके पास या तो रोज़गार है या नौकरी की तलाश में हैं। बेरोजगारी दर श्रम बल में उन लोगों का अनुपात है जिनके पास नौकरी नहीं है। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार, लैंगिक आधार पर दिल्ली में पुरुषों की 57% एलएफपीआर की तुलना में महिला एलएफपीआर 5.5% है, जबकि पुरुषों की 21% की बेरोज़गारी दर की तुलना में महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 47% का है।[2]

वर्ष 2018–19 के आंकड़ों पर गौर करें तो तब भारत की एलएफपीआर 50.2% थी। ऐसा लगता है कि महामारी की वजह से बेरोज़गारी और बढ़ गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के अनुसार, मई 2020 से अगस्त 2020 के बीच एलएफपीआर घटकर 40.2% रह गई। इस समय महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 9.3% थी और इसकी तुलना में पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 67.4% का था। शहरों में महिलाओं की बेरोज़गारी दर 21.9% रही और इसकी तुलना में शहरों में पुरुषों के लिए यह दर 11.7% की थी।[3]

दुनिया भर में और भारत में भी यह बात किसी से छिपी नहीं है कि महिलाओं को बेहतर नौकरियाँ कम ही दी जाती हैं और नौकरियों जैसे ही कम होती हैं उन्हें ही सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। दिल्ली में नौकरियाँ खोजने वाले लोगों (पुराने निवासी और शहर में नए आने वाले दोनों) और नौकरियों की कुल उपलब्धता के बीच गहरी खाई है। पहले से चली आ रही आर्थिक मंदी जैसी स्थिति और अब महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही खराब हुई है। विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष का कहना है कि आने वाले वक्त में इस बात की आशंका प्रबल है कि इस स्थिति का इसका सबसे अधिक ख़ामियाज़ा महिलाओं को ही भुगतना होगा।[4]

इस शोध–अध्ययन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जिसे एक विश्व–स्तरीय शहर कह सकते हैं, में असंगठित क्षेत्र के महिला कर्मियों की स्थिति की समीक्षा की गई है, जहां महिलाओं का रोज़गार की दर वर्ष 1981 से ही लगभग स्थिर रही हैं। यहाँ महिलाओं की कामकाज में भागीदारी लंबे समय से कम दिख रही है, लेकिन महामारी ने तो बची–खुची चीजें भी लगभग खत्म सी कर दी है। इससे निश्चित रूप से दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत सी महिलाओं को अपनी नौकरी या कामकाज को गँवाना पड़ा है। संगठित क्षेत्र में भी महिलाओं ने काफी मुश्किलों का सामना किया है, जिनमें वेतन कटौती से लेकर छटनी तक शामिल हैं। बिना भुगतान वाले घरेलू कार्य का बोझ बढ़ने से संकट और भी बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत में लगभग अधिकृत रूप से 30 लाख महिलाएं है जो घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत है, जबकि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक है।

कोरोना वायरस के संक्रमण और उसकी जटिलता सामने आने के बाद शहरों के अपार्टमेंट के सोसाइटी और कॉलोनियों में घरेलू कामगार यानी घरों में काम करने वाली कामगारों के आने पर रोक लगा दी गई। जहां यह रोक नहीं लगाई गई वहाँ भी लोग संक्रमण के डर से खुद ही उन्हें आने से मना कर दिया। उन्हें यह भी नहीं पता की उनके पैसे उन्हें मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि कई महिलाओं को मार्च के पैसे भी नहीं दिये गये। अप्रैल और मई महीने में जिस समय वह काम नहीं कर पायी उसके पैसे तो उन्हें नहीं मिले, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह चिंता भी खाई जा रही थी की भविष्य में काम बरकरार रहेगा या नहीं? कुछ को जहां मना नहीं किया गया था वहाँ भी वो समय पर साधन नहीं मिलने के कारण नहीं पहुँच पा रहे थे।

घरेलू सहायक महिलाओं से बातचीत के दौरान यह पता चला कि एक घरेलू कामगार महिला को मजदूरी तो कम दिया ही जाता है लेकिन उसके साथ ही साथ भेदभाव भी बहुत होता है। साक्षात्कार के दौरान एक महिला कामगार बबीता ने अपनी आपबीती बताते हुये कहा कि लॉकडाउन हटने के बाद अजीब तरह का भेद–भाव शुरू हुआ है। वे बताती हैं कि घर में घुसते ही सैनेटाइजर से भिंगा देते है। काम के वक्त सभी दूर–दूर रहते हैं। हमें अछूत जैसा महसूस कराया जाता है। कई घरों में तो पहले नहा कर काम शुरू करना पड़ता है। हमारा काम बहुत अच्छा है लेकिन हम लोग बहुत बुरे हैं। घर के मालिक ऐसे पेश आते हैं, जैसे कोरोना का पहला श्रोत हम ही हैं।[5]

दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो नौकरी पर जाने के लिए यात्रा में अधिक समय लगना, कार्य के घंटे और सुरक्षा जैसे मुद्दों से महिलाओं को काफी जूझना पड़ा है जिससे श्रम बल में उनकी हिस्सेदारी में काफी कमी दर्ज की गई है।

उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद गाँव में रहने वाली 42 साल की कल्याणी देवी मुखर्जी नगर और वजीराबाद में तीन घरों में घरेलू कार्य करती हैं। वह अपने बच्चों के साथ अकेले रहती है, पति साथ में नहीं रहता है। उनके घर की आमदनी का एकमात्र स्त्रोत कल्याणी देवी का घरेलू काम ही है। लॉकडाउन की घोषणा होने के दिन ही उसे तीनों घरों के मालिकों ने काम पर आने से मना कर दिया। अपने दुख–दर्द को बयान करते हुए कल्याणी देवी ने बताया कि मैं दस साल से अधिक समय से इन घरों में कार्य कर रही थी और मुझे कुल 7000 रुपये की आमदनी होती थी। अचानक से यह काम खत्म हो गया। लॉकडाउन के दौरान कोई वेतन भी इन लोगों ने मुझे नहीं दिया। बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा, कई दिनों तो भूखे भी सोना पड़ा। लेकिन सरकारी राशन से थोड़ा मदद मिला। जिससे वो आर्थिक एवं मानसिक रूप से टूट चुकी थी, इससे उबरने में काफी समय लगा। लेकिन इसी बीच उसे कोरोना हो गया, जिसके कारण उनका घर से बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया और घर छोटा होने के कारण उन्हे बाकी सभी सदस्यों के साथ ही रहना होता था। जिससे काफी परेशानी हो गई थी। कल्याणी देवी ने बताया कि कारोना काल में काम छूट जाने से रिश्तेदारों एवं परिचितों से कर्ज लेना पड़ा, जिससे वह अभी तक उबर नहीं पाई है।[6]

इसी तरह साक्षात्कार के दौरान एक और घरेलू कामगार महिला से उनकी स्थिति जानने को मिला। पूनम जो एक घरेलू कामगार महिला है जो बिहार के समस्तीपुर जिले से आई है और करीब 15 साल से दिल्ली में अपने चार बच्चे और पति के साथ रह रही है। पूनम घरेलू कामकाज के अलावा पीस

रेटपे कपड़े का धागा कटिंग का भी काम करती है, जिससे वो छः हजार से आठ हजार या कभी कभी नौ–दस हजार भी कमा लेती है। वो जैसे जितना ज्यादा धागा कटिंग करेगी उसी हिसाब से पैसे बनेगेयानि उनके मेहनत के अनुसार आमदनी होती है। पूनम के परिवार का खर्च दोनों पति–पत्नी मिलकर उठाते हैं। कारोना के पहले पूनम का पति एक हार्डवेयर के दुकार पर ठेला पे सामान पहुंचाने का काम करता था। कारोना काल में हालांकि, दिहाड़ी मजदूर के तौर पर नौकरी तो बची रही, लेकिन दोबारा काम शुरू होने में छह महीने लग गए। ये दौर बहुत मुश्किल का दौर था, भोजन तक में कटौतियां करनी पड़ी। मतलब भोजन में दोनों समय बिना सब्जी के खाना खाना, दो या तीन दिनों पे सब्जी खाना। काम बंद रहने पर कुछ दिन तो बचे पैसों से घर का गुजारा कर लिया, परंतु वर्तमान में रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाना उनके लिए बहुत कठिन है। पूनम ने बताया था कि कारोना काल में मेरे बच्चों का पढ़ाई कुछ समय के लिए बंद हो गया था, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट फोन नहीं था। मेरे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक स्मार्टमोबाईल फोन की जरूरत थी। हम इसे नहीं खरीदते तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता, तो हमने फोन के लिए गाँव में रिश्तेदारों से कर्ज लेकर एक स्मार्ट फोन खरीदा। आमदनी कम हो जाने पर पूनम को परिवार चलाने में काफी दिक्कत आई।[7]

ऐसे में घरेलु कामगार महिलाएं आस लगाए बैठी है की काम सुचारु रूप से चले, ताकि उनकी जिंदगी भी आसान हो जाए।

यूएनवूमेन की रिपोर्ट के अनुसार, दुनियाभर में 72% घरेलू कर्मियों ने कोविड–19 महामारी के कारण अपनी नौकरियां खो दी, जिनमें से 80% महिलाएं है। एक से अधिक शिफ्ट में कार्य करना भी बहुत बड़ी चुनौती हो गयी है। उन्हें मजदूरी न दिए जाने के अलावा भी तरह–तरह के कटु अनुभवों का रिपोर्ट भी देखने को मिला है। अभी तक इन कामगारों के हित में कोई कानून नहीं है। न तो इन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलती है न ही साप्ताहिक छुट्टी जैसी कोई लाभ।8

तालिका–1. अध्ययन हेतु चुनी गई घरेलू कामगार महिलाओं के करोना काल (वर्ष 2020) के दौरान के आय का मासिक ब्यौरा

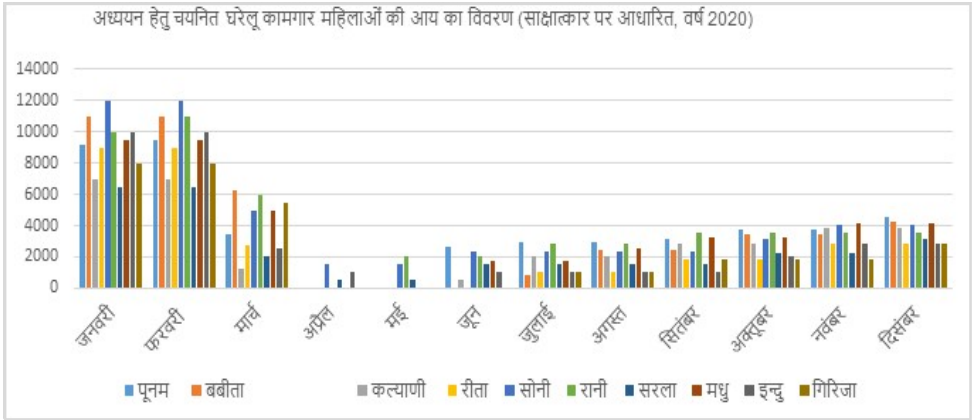

उपरोक्त तालिका में हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जितनी भी घरेलू कामगार महिलाएं हैं, उनकी आय करोना काल के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ। जहां मार्च 2020 से उनकी आय में

80 से 100 प्रतिशत तक की कमी आई। वहीं जून 2020 से जब करोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन को धीरे–धीरे हटाया जाने लगा, उसी के साथ घरेलू महिलाओं को भी थोड़ा–थोड़ा काम मिलना प्रारम्भ हुआ। लेकिन यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि लॉकडाउन के बाद भी किसी भी घरेलू कामगार महिला को दिसंबर 2020 तक महामारी से पूर्व वाली आय के बराबर आय नहीं हो पाया। इससे स्पष्ट है कि महामारी ने इन महिलाओं को आर्थिक रूप से काफी लंबे समय तक नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही इन्हें कई मानसिक समस्याओं से भी दो–चार होना पड़ा।

इस अध्ययन से जुड़े तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि घरेलू कामगार के तौर पर काम करने वाली महिलाओं को अक्सर दुर्व्यवहार और शोषण का सामना करना पड़ता है। उन्हें वे बुनियादी अधिकार भी नहीं मिलते जो सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए तय किए गए हैं। आखिर उन्हें इस शोषण से कब छुटकारा मिलेगा? इस स्टडी का निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि भारत में घरेलू कामगार महिलाएं काफी कम वेतन एवं सामाजिक असुरक्षा के बीच काम करती हैं। इस स्थिति को कारोना जैसे महामारी इनके जीवन को और भी कठिन बना दिया। इन परिस्थितियों को देखते हुये हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे इन महिलाओं के कार्य को उनकी सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से कानूनी ढाल प्रदान किया जाय, ताकि इनके सामाजिक सुरक्षा के साथ ही साथ इनके शोषण को भी नियंत्रित किया जा सके।

इसके साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि कार्य में लैंगिक असमानताओं को दूर करें एवं बड़े स्तर पर महिला उन्मुखी लघु एवं कुटीर उद्धोग की स्थापना की जाय। महिला के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए नीति बनाई जाए, ताकि असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों का विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बरकरार रहे एवं संकट के समय उनके सामने ऐसी स्थिती ना आये कि वो दाने–दाने के लिए मोहताज हो जाए और एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना पड़े।

संदर्भ

1. सिन्हा, पी0आर0. (2011). इंदुबाला, श्रम एवं समाज कल्याण. भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीबूटर्स।
2. भारत. (2012). ''वार्षिक संदर्भ ग्रंथ''. सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
3. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/women-labour-participation-in-india.
4. https://www.academia.edu/11316235/Socio_Economic_Conditions_of_the_people_Living.
5. लोकसभा सचिवालय. (2014). शोध एवं सूचना प्रभाग. असंगठित कामगारः मुद्दे और चुनौतियाँ. दिसम्बर।
6. (2020). Policy Brief: the impact of Covid –19 on women. United Nations. 9 April.
7. कुमारी, ममता. ''घरेलू महिला कामगार के बहाने कुछ बातें''. हिन्दी समय. महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालयः वर्धा, महाराष्ट्र।